भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1514

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2022 को दिया जाना है।

.....

उत्तर प्रदेश में अटल भूजल योजना

1514. श्री राजेश वर्मा:

श्री प्रदीप कुमार चौधरीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जिन क्षेत्रों में 'अटल भूजल योजना' कार्यान्वित की जा रही है, उन क्षेत्रों में ऐसी कृषि पद्धतियों, जो भूजल से संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, को बदलने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) अटल भूजल योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ग) उत्तर प्रदेश में अटल योजना के कार्यान्वयन की सीतापुर जिले सहित जिला-वार स्थिति क्या है और इससे लाभान्वित होने वाले जिलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को इस योजना से जोड़ा गया है और इस संबंध में कार्य की स्थिति क्या है;

(ङ) क्या उत्तर प्रदेश में भूजल स्तर में गिरावट की दर को रोकने में सरकार को सफलता मिली है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टूडू)

(क): अटल भूजल योजना, सामुदायिक नेतृत्व वाले सतत भूजल प्रबंधन को विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से लक्षित करता है जिसमें कुशल सिंचाई पद्धतियां और फसलों का उचित चयन शामिल है।

इस योजना के तहत चयनित क्षेत्र में कृषि पद्धतियों में परिवर्तन लाने के लिए, मौजूदा ग्राम और जल स्वच्छता समितियों के माध्यम से समुदायों को जुटाया गया है और क्षेत्र में जल के उपयोग और उपलब्धता के बारे में जागरूक किया गया है और जल बजट तैयार किए जा रहे हैं। इन जल बजटों से जल सुरक्षा योजनाओं (डब्ल्यूएसपी) का आधार निर्माण होता है, जो इस योजना का आधार हैं। डब्ल्यूएसपी में विभिन्न मांग पक्ष के कार्यकलाप होते हैं जैसे कि सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, पाइपलाइनों का उपयोग और साथ ही आपूर्ति पक्ष के कार्यकलाप जैसे चेक बांध, फार्म पॉण्ड, रिचार्ज शाफ्ट और अन्य कृत्रिम पुनर्भरण/जल

संरक्षण संरचनाएं, जो समुदाय द्वारा प्रस्तावित हैं जो जागरूकता निर्माण और क्षमता निर्माण अभ्यास पर आधारित होते हैं जिसे इस योजना में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी ग्राम पंचायतों में जल की मांग के प्रबंधन के संदर्भ में समुदाय में व्यवहारिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से केंद्रित सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान भी आयोजित किए जा रहे हैं। यह योजना कुछ पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद प्रोत्साहन भी प्रदान करती है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, कृषि में किसी भी नवीन प्रथाओं में उपयोग की जा सकती है जो जल की बचत करती है या जल के उपयोग की दक्षता को बढ़ाती है।

(ख): इस योजना के तहत 2022-23 के बजट के लिए 700 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है।

(ग) और (घ): यह योजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चार जिलों मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और मेरठ सहित उत्तर प्रदेश के 10 जिलों के 26 ब्लॉकों की 550 ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित की जा रही है। सीतापुर में इस योजना का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। इन चार जिलों में कुल 200 सामुदायिक नेतृत्व वाली जल सुरक्षा योजनाएं (डब्ल्यूएसपी) तैयार की गई हैं। संबंधित लाइन विभागों द्वारा विभिन्न केंद्र/राज्य सरकार की योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से समुदायों की सक्रिय भागीदारी के साथ डब्ल्यूएसपी का क्षेत्र में कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ङ) और (च): अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के संदर्भ में, इस योजना ने विभिन्न जागरूकता पैदा करने वाली गतिविधियों के माध्यम से समुदायों के व्यवहार में परिवर्तन लाया है। यह योजना अभी उस चरण तक नहीं पहुंची है जहां भूजल स्तर में ह्रास की दर को रोका जा सके। हालाँकि, हाल ही में केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा प्रकाशित भूजल स्रोत आकलन 2022 के अनुसार, भारत सरकार के प्रयासों से, इस योजना सहित, उत्तर प्रदेश के कुछ ब्लॉक जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर आदि में सुधार हुआ है।

******